

अपील पुत्र समूह जाति माली निवासी तलावड़ा तहसील गंगपुर सिटी
बनाम

—अपीलार्थी

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावड़ा

—रेस्पोंडेण्टस

निर्णय

दिनांक- 11/02/2017

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा मिसल संख्या 492/15 में पारित निर्णय दिनांक 21/09/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम तलावड़ा के खसरा नं० 342/1574 रकबा 0.28 है० किस्म बरानी का अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझौते की भावना से यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। वकील अपीलान्त उप० एवं रेस्पोंडेण्टस की और से परोकार सरकार उपस्थित। सुलह समझौते के तहत समय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि धारा 91 एल आर एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने के उपरांत ही सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जा सकता है जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता हों एवं उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्त का कोई अतिक्रमण ही। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/09/15 निरस्त फरमाने का श्रम करे।

विद्वान राजकीय परोकार ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा अतिक्रमी द्वारा वाद आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर ही उक्त निर्णय सुनाया गया है। अतिक्रमी का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अतिक्रमी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/09/15 यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी व परोकार राज की सुनवाई सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यो व अपीलार्थीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त का वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित कोई रिपोर्ट व निर्णय संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त को पूर्व अतिक्रमी माना जा सके।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बेदखली, शास्ति व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर